THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) During current year, a central subsidy of 30% to private and public sectors and 40% to government and nonprofit making organisations is available for the installation of low grade solar thermal devices such as solar water heating systems. A maximum subsidy of Rs. 3000, Rs. 150 and Rs. 1050 is available for Domestic Water Heater, Solar Cooker and Community Solar Cooker respectively.

Solar Photovoltaic Programme is, however, being implemented as a demonstration programme by State Nodal agencies, with financial assistance from the Central Government.

जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसियों के प्रस्तुत किए जाने पर धन का लौटाया जाना

*12. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ऐसे पालिसी-धारकों को समय पर धन की अदायगी नहीं करता है, जो अपनी पालिसियों को परिपक्वता अवधि के पूर्ण होने पर प्रस्तुत करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निगम के सान्ताक्रुज, मुम्बई स्थित कार्यालय में ऐसे पालिसी-धारकों की संख्या कितनी है, जिन्होंने 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अपनी पालिसियां प्रस्तुत की हैं;

(घ) ऐसे पालिसी धारकों की संख्या कितनी है, जिसके मामले में धनराशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ङ) ऐसे दावों की संख्या कितनी है जिनका अभी तक निपटान नहीं किया गया है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अपनी पालिसियां प्रस्तुत करने वाले पालिसीधारकों को दावा-राशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1.4.1991 से 31.12.1991 तक की अवधि के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के सांताक्रुज, बम्बई कार्यालय द्वारा पालिसियां प्रस्तुत (अभ्यर्पित) करने के संबंध में अपने पालिसीधारकों से 6282 आवेदन-पत्र प्राप्त किए गए जिनकी सब औपचारिकताएं उचित रूप से पूरी कर दी गई थीं।

(घ) उपर्युक्त 6282 मामलों में से 6280 मामलों में प्रस्तुत पालिसियों की राशि पालिसी-धारकों को अदा कर दी गई है।

(ङ) और (च) 6282 मामलों में से केवल दो मामले ऐसे हैं जो संबंधित रिकार्ड के अभाव में लम्बित पड़े हैं। इन दोनों मामलों को यथासम्भव शीघ्र निपटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में संचार की अपर्याप्त सुविधाएं

*13. **कुमारी आलिया:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले में कुछ गांवों को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर डाक और टेलीफोन-सुविधाओं का लगभग अभाव बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1991-92 के वर्ष के दौरान देश में कितने गांवों में संचार सुविधाएं सुलभ कराई गई हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी नहीं। जहां तक डाक सुविधाओं का संबंध है, फैजाबाद जिले की स्थिति काफी अच्छी है। फैजाबाद जिले में एक डाकघर द्वारा जितने औसत क्षेत्र और जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है वह क्रमशः 7.07 वर्ग कि॰ मी॰ और 4567 व्यक्ति हैं। इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत क्रमशः 22.10 वर्ग कि॰ मी॰ क्षेत्र और व्यक्तियों की संख्या 4607 है।

फैजाबाद जिले में, जहां तक टेलीफोन सुविधा का संबंध है, इस जिला मुख्यालय, सभी तहसील मुख्यालयों, 18 ब्लॉक मुख्यालयों और 63 ग्राम पंचायतों में ये सुविधा इस समय उपलब्ध है। इसके अलावा, देश की सभी ग्राम पंचायतों को मार्च, 1995 तक टेलीफोन सुविधा उत्तरोत्तर प्रदान करने का प्रस्ताव है जिनमें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले की ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण इलाकों के लिए अब तक 660 अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की मंजूरी दी जा चुकी है और अन्य 238 मामलों में मंजूरी जारी की जा रही है।

23.2.92 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में 13,477 पंचायत-ग्रामों को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है।

Payment of DA to Central Government Employees

*14. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to State;

(a) what is the precentage of Deamess Allowance that has become due to the Central Government employees with effect from the 1st January, 1992;

(b) whether Government propose to issue necessary instructions for payment of next instalment of Dearness Allowance;

(c) if so, by when and if not, the reasons therefor;

(d) whether the Dearness Allowance would be paid in cash: and

(e) if no, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a): The percentage of additional instalment of Dearness Allowance due to the Central Govt, employees from 1.1.92 is as follows :-

Pay Range		Percentage
Basi pay upto p.m.	Rs. 3500/-	11%
Basi pay above and upto Rs. 6000/-	Rs 3500/- p.m	8%
Basi Pay above p.m.	Rs 6000/-	7%

(b) and (c) As per existing instructions, the instalment of Dearness Allowance due from 1st January becomes paybale with the salary of March.

(d) and (e) The mode of payment will be decided when the instalment becomes payable.

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव

*15. **श्री अजीत जोगी:**
कुमारी सुशीला तिरिया:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के निर्यात और आयात पर रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो रुपये के अवमूल्यन के पश्चात 15 फरवरी, 1992 तक डॉलर के रूप में आयात और निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई है;

(ग) क्या रुपये के अवमूल्यन का उन देशों के साथ हमारे व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जोकि रुपये में भुगतान स्वीकार करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ऐसे देशों के साथ व्यापार-संबंधों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, हां। तथापि, यह बताने की आवश्यकता है कि निर्यात केवल अवमूल्यन पर ही आधारित नहीं होते हैं बल्कि विश्व के व्यापार का वातावरण, घरेलू उत्पादन, निर्यातों के लिए बेशी की उपलब्धता, निर्यात उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण आयातित कच्चे माल तथा पूंजीगत वस्तुओं की उपलब्धता, ऋण की उपलब्धता तथा निर्यातकों को अधोमान्य ब्याज की दरें आदि जैसे अन्य कई कारकों पर भी निर्भर करते हैं। इसी प्रकार आयात, आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, आवश्यक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में कमी, औद्योगिक क्रियाकलाप, आदि से भी संबंधित हैं। यह उल्लेख करने की भी आवश्यकता है कि अवमूल्यन के प्रभाव को तत्काल ही महसूस नहीं किया जाता, अपितु, ऐसे प्रभाव के लिए समय अंतराल होता है।

(ख) भारत के विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़े अप्रैल-दिसंबर, 1991 तक उपलब्ध हैं। एक विवरण-पत्र, अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट CLXII , अनुपत्र संख्या 1]

(ग) वर्ष 1991 में रुपया भुगतान देशों को भारतीय निर्यातों में समस्त रूप में कमी मुख्य रूप से भूतपूर्व यू०एस०एस०आर० में बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण थी न कि रुपए के अवमूल्यन के कारण।

(घ) हमारी कार्यनीति स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमण्डल (सी०आई०एस०) के अलग-अलग गणराज्यों तथा रुपया भुगतान क्षेत्र के अन्य देशों जैसे चैकोस्लोवाकिया तथा रोमानियां से निपटने का है। हमारी भावी निर्यात कार्यनीति में ये तत्व शामिल होंगे: परिवर्तित आर्थिक वातावरण में अत्यधिक विपणन बल, नई संभावनाओं का उपयोग